ईसरदा बांध का 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण, इस मानसून में होगा जल संग्रहण : भास्कर ए सावंत

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रदेश के हर छोर तक सुचारू पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कर रहे है। मुख्यमंत्री के निर्देशन में सवाई माधोपुर और दौसा जिले में पेयजल आपूर्ति की दृष्टि से महत्वपूर्ण ईसरदा बांध का निर्माण कार्य मिशन मोड़ पर किया जा रहा है। बांध के निर्माण का 90 फीसदी कार्य पूर्ण हो चुका है। बांध के पियर्स एवं गेटों का कार्य पूरा हो चुका है। डैम एवं कॉक्रीट स्पिलवे का कार्य 15 जून तक पूर्ण किये जाने का प्रयास है।

इसी के तहत शनिवार को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव भास्कर ए सावंत ने ईसरदा बांध परियोजना के निर्माण कार्य, फिल्टर प्लांट साइट के कार्यों का निरीक्षण किया। साथ ही, विभागीय अभियंताओं को कार्य प्रगति को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने प्रभावित परिवारों को भूमि आवंटन, पुनर्वास अवार्ड कार्य की पूर्णता को समयबद्ध सीमा में पूर्ण करने पर जोर दिया। भूमि अधिग्रहण से संबंधित प्रकरण, रेलवे एवं वन विभाग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा कर इनका शीघ्र समाधान किये जाने की बात कही।

इस दौरान उपखंड अधिकारी उनियारा शत्रुघन गुर्जर, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता राजसिंह, अधीक्षण अभियंता टोंक राजेश गोयल, बीसलपुर परियोजना के अधीक्षण अभियंता मनोज सिंह, ईसरदा बांध के अधीक्षण अभियंता विजय शर्मा, अधिशाषी अभियंता विकास गर्ग, सहायक अभियंता अभिषेक लसाड़िया समेत अन्य मौजूद रहे।

जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव भास्कर ए सावंत ने ईसरदा डैम का निरीक्षण किया।

ईसरदा बांध बीसलपुर बांध के डाउन स्ट्रीम में ग्राम बनेठा (तहसील उनियारा) टोंक के पास बनास नदी पर बनाया जा रहा है। इसका निर्माण दो चरणों में किया जाना है। प्रथम चरण में डैम का निर्माण पूर्ण भराव स्तर 262 आरएल मीटर (भराव क्षमता 10.77 टीएमसी) तक पूर्ण किया जाएगा। इसमें पानी का भंडारण 256 आरएल मीटर भराव क्षमता 3.24 टीएमसी है। दूसरे चरण में बांध में पूर्ण भराव क्षमता 262 आरएल मीटर तक पानी संग्रहित हो सकेगा।

आगामी मानसून के दौरान बांध में जल संग्रहित किया जा सकेगा। इसके बाद दौसा के 1 हजार 79 ग्राम और 5 शहरों तथा सवाई माधोपुर के 1 शहर तथा 177 गांवों में पेयजल की सुचारू आपूर्ति हो सकेगी। यह परियोजना जल संकट समाधान के साथ बीसलपुर बांध के अधिशेष पानी और बनास नदी के बारिश के जल का कुशल प्रबंधन भी

- **अभियंताओं को समयबद्ध सीमा में कार्य पूर्ण करने के दिए निर्देश**

सुनिश्चित करेगी। साथ ही, ईसरदा बांध से रामजल सेतु लिंक परियोजना (संशोधित पीकेसी-ईआरसीपी लिंक परियोजना) के तहत अन्य बांधों को पेयजल के लिए आपूर्ति हो सकेगी।

बांध निर्माण में ओवरफ्लों वाले भाग में स्पिलवेय ब्रिज में स्लैब निर्माण का कार्य प्रगतिरत है। अभी तक 28 के विरुद्ध 28 स्लैब डाली जा चुकी है। साथ ही, 28 पीयर्स के विरुद्ध 28 पियर्स वांछित ऊंचाई तक पूर्ण किए जा चुके है। बांध में 84 गर्डर के विरुद्ध 84 गर्डर लॉन्च किए गए है। बांध में 28 ब्लॉक एप्रेन के विरुद्ध 23 ब्लॉक एप्रेन का निर्माण किया जा चुका है। बांध में 28 पावर पैक रूम के विरुद्ध 28 पावर पैक रूम और 28 रेडियल गेट के विरुद्ध 28 रेडियल गेट का निर्माण हो गया है। बांध में 56 हाइड्रोलिक सिलेंडर के विरुद्ध 56 हाइड्रोलिक सिलेंडर भी लगाए जा चुके हैं। मिट्टी के बांध का कार्य लगभग 82 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। मुख्य बांध का कार्य लगभग 90 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है।

मुख्यमंत्री भगवान परशुराम की महाआरती में शामिल हुए

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार को राजस्थान ब्राह्मण महासभा जयपुर महानगर की ओर से आयोजित भगवान परशुराम की शोभायात्रा और महाआरती कार्यक्रम में शामिल हुए। शर्मा ने प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर विधायक कालीचरण सराफ एवं बालमुकुंदाचार्य सहित ब्राह्मण समाज के गणमान्य लोग तथा बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।

साइबर सिक्योरिटी में भी सर्वश्रेष्ठ बनेगा राजस्थान : राज्यवर्धन राठौड़

जयपुर। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ की अध्यक्षता में योजना भवन में शनिवार को आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में साइबर सिक्योरिटी को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए व्यापक रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक में तकनीकी उन्नित, मानव संसाधन और प्रक्रियाओं के विकास पर चर्चा की गई।

आईटी मंत्री कर्नल राठौड़ ने बैठक में साइबर सिक्योरिटी के लिए समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि साइबर सिक्योरिटी केवल सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर तैयार करने तक सीमित नहीं है। इसके लिए तीन प्रमुख तत्वों-पीपल (लोग), प्रोसेस (प्रक्रियाएं) और टेक्नोलॉजी (प्रौद्योगिकी) का समन्वय जरूरी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि केवल तकनीक पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। इसके लिए स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देना होगा ताकि विदेशी निर्भरता कम हो।

कर्नल राठौड़ ने बैठक में मानव संसाधन के विकास पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि साइबर सिक्योरिटी से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों की दक्षता बढ़ाने के लिए संरचित और असंरचित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हर दिन प्रशिक्षण, जागरूकता का विस्तार और ग्रूमिंग होनी चाहिए। इसके लिए पर्याप्त बजट प्रावधान भी किए जाएंगे, जिससे सर्टिफाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के माध्यम से कर्मचारियों की क्षमता को और निखारा जा सके। इससे न केवल कर्मचारियों की तकनीकी दक्षता बढ़ेगी, बल्कि उनकी पेशेवर

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने योजना भवन में शनिवार को उच्चस्तरीय बैठक ली।

मूल्यवृद्धि भी होगी। साथ ही कार्य संस्कृति में सुधार होगा, जो दीर्घकालिक रूप से विभाग की कार्यक्षमता को बढ़ाएगा।

राठौड़ ने राजस्थान के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को देश का सर्वश्रेष्ठ बनाने का संकल्प दोहराया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नया भारत, मजबूत भारत है। हम नई सोच और दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि राजस्थान का आईटी विभाग राष्ट्रीय स्तर पर एक मिसाल बने। इस दिशा में विभाग ने एक निश्चित समयावधि में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की योजना बनाई है। कर्नल राठौड़ ने भामाशाह डेटा सेंटर का उदाहरण देते हुए कहा कि यह वर्तमान में देश के अन्य राज्यों की तुलना में कहीं अधिक सुरक्षित और उन्नत है। यह डेटा सेंटर न केवल तकनीकी रूप से सक्षम है, बल्कि साइबर खतरों से डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है।

बैठक में प्रतिष्ठित साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ और पूर्व सैन्य अधिकारी कर्नल निधीश भटनागर ने साइबर सिक्योरिटी के संबंध में प्रजेंटेशन के माध्यम से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में साइबर अपराधी हर दिन चालाक बनते जा रहे हैं। ऐसे में आईटी प्रोफेशन से जुड़े हर व्यक्ति को भी हर दिन अपडेट और सतर्क रहने की आवश्यकता है।

बैठक में सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ ही, ऊर्जा, जयपुर विकास प्राधिकरण, सहकारिता, भूजल संसाधन, परिवहन, आबकारी विभागों के अलावा आरजीएचएस और आईएफएमएस परियोजना आदि से जुड़े विभिन्न अधिकारीगण उपस्थित थे।

हनुमान बेनीवाल का बिगड़ा मानसिक संतुलन : कन्हैया लाल चौधरी

जयपुर। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने कहा कि नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल खींवसर में चुनाव हारे हैं, तब से मीडिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए बचकानी हरकतें कर रहे हैं। चौधरी ने कहा कि हमारी पार्टी ने मजबूती से मिलकर खींवसर विधानसभा का उपचुनाव लड़ा और जीते तथा खींवसर में हनुमान बेनीवाल एवं उनके पार्टी कार्यकर्ता जिस तरह से गुंडागर्दी करते थे, ब्लैकमेलिंग करते थे, उसका खात्मा किया।

उन्होंने कहा कि बेनीवाल ओछी लोकप्रियता पाने के चक्कर में मीडिया में लगातार अनर्गल बयान देते रहते हैं।

आरएमएससीएल को एलीट्स स्मार्ट गवर्नमेंट एक्सीलेंस अवार्ड

जयपुर। राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आरएमएससी) को वर्ष 2025 के प्रतिष्ठित एलीट्स स्मार्ट गवर्नमेंट एक्सीलेंस अवार्ड-2025 से सम्मानित किया गया है। एलिट्स टेक्नोमीडिया एण्ड एडिटर इन चीफ, ई-गवर्नमेंट मैगजीन, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग तथा कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित समारोह में आरएमएससीएल को यह पुरस्कार दिया गया। आरएमएससीएल को यह पुरस्कार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में ई-औषधि एवं ई-उपकरण सॉफ्टवेयर सहित अन्य तकनीकी नवाचारों के लिए प्रदान किया गया है।

छात्रवृत्ति आवेदनों में रेड फ्लैग 15 मई तक हटा सकेंगे

जयपुर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर ग्रामीण में लगभग साढ़े चार हजार से ज्यादा छात्रवृत्ति आवेदनों में लगाए गए रैड फ्लैग को हटाने के लिए विभाग की ओर से एक अंतिम मौका दिया गया है, जिसके बाद यदि आवेदकों ने इन आवेदनों में संशोधन नहीं कराया तो इन आवेदनों को विभाग की ओर से निरस्त कर दिया जाएगा।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक जितेन्द्र कुमार सेठी ने बताया कि शैक्षिणक सत्र 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 में छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को अभी तक छात्रवृत्ति नहीं मिली तो वह एक बार पोर्टल पर एप पर लॉगिन कर आवेदन को चैक कर लें, क्योंकि विभाग की ओर से बड़ी संख्या में छात्रवृत्ति चाहने वालों को 'रैड फ्लैग' से

- **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने जयपुर ग्रामीण में चार हजार से अधिक आवेदकों को दिया अवसर**

मार्क कर दिया था।

जितेन्द्र कुमार सेठी ने बताया कि एक बार छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने के बाद जन आधार से डाटा फैच करने पर एवं आवेदन में किसी प्रकार का बदलाव किया जाता है तो उसे 'लाल निशान' लगा दिया जाता है। जैसे किसी छात्र ने नाम, जन्म तिथि, आधार संख्या, जन आधार संख्या या फिर अन्य कोई बदलाव किया तो उसे संदिग्ध मान लिया गया। इस कारण सत्र 2022-23 और 2023-24 के रैड फ्लैग वाले छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली थी।

इन छात्रों को ऑनलाइन ही नोटिस भी दिया गया है। एवं एसएमएस व दूरभाष के माध्यम से भी सूचना करी गई लेकिन अभी तक बड़ी संख्या में छात्र ऐसे हैं, जिन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया है। ऐसे में इन छात्रों को 15 मई तक का समय दिया है।

उन्होंने बताया कि ऐसे छात्रों को जयपुर ग्रामीण के विभागीय कार्यालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर ग्रामीण जिला परिषद जयपुर बनी पार्क एरिया में संपर्क कर अपने दस्तावेज जमा कराने होंगे। दस्तावेजों की जांच के बाद सही पाने पर रैड फ्लैग हटाने की प्रक्रिया की जाएगी। अन्यथा 15 मई के बाद इन आवेदनों को निरस्त कर दिया जाएगा।

ग्रीष्मकालीन मिलावट विरोधी अभियान में एक मई तक लिए 6280 नमूने

जयपुर। निरामय राजस्थान के उद्देश्य के साथ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाया जा रहा ग्रीष्मकालीन मिलावट विरोधी अभियान प्रदेशभर में सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है। अभियान के तहत निर्धारित लक्ष्यों से अधिक प्रगति दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल एवं चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर के मार्गदर्शन में 19 मई से 5 मई तक चलाए जा रहे इस अभियान के प्रथम चरण में 6 हजार नमूने लिए जाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसके विरूद्ध 1 मई तक 6280 नमूने लिए जा चुके हैं।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि गर्मी के मौसम में मिलावट एवं खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के प्रभावित होने के मामले अधिक सामने आते हैं। इसे देखते हुए विभाग ने मिलावट विरोधी विशेष अभियान संचालित किया है। अभियान के तहत 1 मई तक 2575 निरीक्षण कर 6280 नमूने लिए गए हैं। इनमें 2545 एन्फोर्समेंट एवं 3735 सर्विलेंस सैम्पल शामिल हैं। ये नमूने प्रमुखतः डेयरी उत्पाद, बर्फ, पेय पदार्थ, मिठाइयों, फल व सब्जियों के हैं।

राठौड़ ने बताया कि निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थों की निर्माण इकाइयों पर विशेष फोकस किया गया है। एक मई तक 1140 निर्माण इकाइयों पर निरीक्षण किया गया है। अनियमितता पाई जाने पर करीब 42 निर्माताओं के यहां जब्ती एवं 64 निर्माताओं के यहां नष्टीकरण की कार्रवाई की गई है। इसी ्रपकार 374 खुदरा विक्रेताओं के यहां निरीक्षण किया गया है।

प्रमुख शासन सचिव ने बताया कि निरीक्षण की कार्यवाही सर्वाधिक मिलावट वाले संभावित स्थानों पर केंद्रित रही है। इसके तहत 1 मई तक बस स्टैण्ड पर 333, रेलवे स्टेशन पर 185, हाईवे फूड प्वाइंटस पर 441 एवं मॉल स्थित फूड प्लाजा आदि पर 103 नमनूे लिए गए हैं। अभियान के तहत की जा रही कार्रवाई की नियमित रूप से राज्य स्तर से मॉनिटरिंग की जा रही है।

मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का दायरा बढ़ने से आमजन को मिलेगा उच्च स्तरीय उपचार : खींवसर

जयपुर। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने कहा कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का नवीन चरण स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक उन्नत एवं बेहतर बनाएगा। योजना का दायरा बढ़ने और इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी लागू होने से आमजन को अत्याधुनिक एवं उच्च स्तरीय उपचार मिलेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे राज्य सरकार की इस योजना का बेहतरीन ढंग से संचालन सुनिश्चित करें और रोगियों को निर्बाध रूप से इसका लाभ दिलाएं।

खींवसर शनिवार को स्वास्थ्य भवन में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के नए चरण के बेहतर एवं सुगम क्रियान्वयन को लेकर आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गरीब एवं जरूरतमंद सहित अन्य वर्गों के लिए मा योजना जीवनदायी पहल है। राज्य सरकार ने इस वित्तीय वर्ष के बजट में इस योजना का दायरा इतना विस्तृत कर दिया है कि अब सामान्य बीमारी से लेकर रोबोटिक सर्जरी तक का उपचार इस योजना में मिल रहा है। अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि योजना के क्रियान्वयन में किसी तरह की लापरवाही नहीं हो और सूचीबद्ध चिकित्सा संस्थानों में इस योजना का गुणवत्ता के साथ पूरा लाभ मिले।

चिकित्सा मंत्री ने कहा कि योजना के तहत क्लेम के त्वरित एवं सरल निपटान की प्रक्रिया अपनाई जाए। चिकित्सा संस्थानों में उपचार की

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने स्वास्थ्य भवन में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के नए चरण के बेहतर एवं सुगम क्रियान्वयन को लेकर आयोजित बैठक को संबोधित किया।

प्रक्रिया को भी अधिक सुगम बनाया जाए, ताकि लोगों को उपचार आसानी से और समय पर मिले। उन्होंने कहा कि यह राजस्थान के लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि अब अन्य राज्यों के लोग भी यहां उपचार के लिए आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना के माध्यम से आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं और निजी अस्पतालों की उपलब्धता का लाभ आमजन को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि विभिन्न हितधारकों के सहयोग से इस योजना की दक्षता में वृद्धि होगी।

खींवसर ने विभिन्न बीमा सेवा प्रदाताओं से संवाद किया और प्रतिस्पर्धी कंपनियों का गहन विश्लेषण भी किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान स्वास्थ्य बीमा की दृष्टि से देश का अव्वल राज्य है। हमारा फोकस है कि स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से प्रदेश के हर नागरिक की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित हो। लोग इलाज के खर्च चिंता मुक्त हों और उन्हें विश्व स्तरीय उपचार की सुविधाएं निःशुल्क मिलें।

खींवसर ने कहा कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली की रीढ़ है और इसका भविष्य उज्ज्वल है। यह योजना ना केवल लोगों को गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवा रही है, बल्कि राज्य की चिकित्सा व्यवस्था को भी एक नई दिशा दे रही है। योजना से निजी एवं राजकीय क्षेत्र के अस्पतालों की आय में वृद्धि होने के साथ ही उनमें उच्च स्तरीय सुविधाओं का विकास भी संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि योजना से संबद्ध निजी अस्पताल पूरी पारदर्शिता

- **स्वास्थ्य बीमा से हर नागरिक की स्वास्थ्य सुरक्षा पर फोकस होगा**

और जीवन रक्षा की भावना के साथ इस योजना का लाभ आमजन को दें। किसी भी स्तर पर कोई अनियमितता नहीं हो। अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि सभी अस्पतालों को क्लेम का भुगतान समयबद्ध रूप से हो।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि प्रदेशभर में योजना का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। पैकेज की संख्या बढ़ने, अस्पतालों के एम्पेनलमेंट के नियमों को सरल करने तथा इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी जैसे प्रावधान लागू होने से अब योजना का संचालन और बेहतर हुआ है। हमारा प्रयास है कि योजना के संचालन की प्रक्रियाएं अधिक जनोन्मुखी हों ताकि राजधानी से लेकर गांव-कस्बों तक इसका ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिले।

राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेंसी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती प्रियंका गोस्वामी ने योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि योजना में करीब 1 करोड़ 34 लाख परिवार पंजीकृत हैं। प्रतिदिन औसतन 8 हजार लोगों को इस योजना से लाभ मिल रहा है। अब योजना में पैकेज की संख्या 1800 से बढ़कर करीब 2300 हो गई है।

एनसीआर में बीएस-4 वाहनों का संचालन रोकने के आदेश पर रोक

जयपुर। राजस्थान हाई कोर्ट ने एनसीआर में दस साल तक के डीजल वाहनों को चलाने की अनुमति होने के बावजूद एनसीआर के भरतपुर क्षेत्र में सात साल पुराने बीएस-4 और यूरो-2 वाहनों का संचालन रोकने और केवल बीएस-6 व यूरो-4 वाहनों का ही संचालन करने की अनुमति देने के परिवहन विभाग के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में परिवहन आयुक्त, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, एनसीआर सचिव और क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, भरतपुर को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस अनिल उपमन की एकलपीठ ने यह आदेश मॉर्डन स्कूल व अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता संस्थानों ने स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों के आवागमन के लिए साल 2019 में बस खरीद कर उसका भरतपुर आरटीओ से रूट परमिट लिया था। वहीं रूट परमिट की अवधि पूरी होने पर आरटीओ ने उनका नवीनीकरण प्रार्थना पत्र खारिज कर याचिकाकर्ताओं को बीएस-6 व यूरो-4 वाहन ही संचालित करने को कहा। याचिका में कहा गया कि एनजीटी ने 7 अप्रैल, 2015 को दिल्ली और एनसीआर में दस साल पुराने डीजल वाहनों का संचालन नहीं करने को कहा था।

देवनानी पहुंचे शिव महापुराण कथा में

जयपुर। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी शनिवार को विद्याधर नगर स्टेडियम में आयोजित सात दिवसीय शिव महापुराण कथा में पहुंचकर पंडित प्रदीप मिश्रा को दुपट्टा व शॉल ओढाकर कर और माला पहनाकर उनका आशीर्वाद और कथा का प्रसाद प्राप्त किया।

देवनानी ने कहां कि अंतरराष्ट्रीय कथा प्रवक्ता, भागवत भूषण पं. प्रदीप मिश्रा (सीहोर वाले) के श्री मुख से पावन कथा का वाचन हो रहा है। श्री शिव महापुराण कथा में प्रतिदिन लाखों श्रद्धालुओं की उपस्थिति और श्रद्धा भाव अद्भुत है। पं. प्रदीप मिश्रा भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़े प्रसंगों में अमर कथा के रहस्य रोचकता के साथ उजागर कर रहे हैं।